मोहम्मद असलम

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

22 सितंबर, 1976

[पी. एन. भगवती, वी. आर. कृष्णा अय्यर और एस. मुर्तजा फजल अली, जे. जे.]

तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद उच्चतम न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अभ्यास और प्रक्रिया-पुनर्मूल्यांकन, उचित जब न्याय की विफलता हुई हो।

अपीलार्थी, शाहजहांपुर जिले के एक ग्रामीण खंड विकास कार्यालय में एक कैशियर को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराया गया था। दोनों अदालतों ने एक साथ पाया कि उन्होंने उस राशि को गलत तरीके से जेब में डाल लिया, जिसके बारे में उन्होंने पंचायत-सचिव को वेतन के रूप में देने का दावा किया था।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उपरोक्त भुगतान के संबंध में वाउचर और नकद रजिस्टर की नियमित प्रविष्टि द्वारा उसके खिलाफ आरोप गलत साबित किया गया था, जिसे खंड विकास अधिकारी द्वारा गलत तरीके से चिह्नित किया गया था और शुरू किया गया था, और सबूत में पेश किया गया था।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय अभिनिर्धारित किया:

(1) तथ्य के निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय स्तर पर मुकदमेबाजी की अंतिमता के प्रस्ताव की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन नियम को साबित करने वाले अपवाद भी अच्छी तरह से स्थापित हैं। दोनों न्यायालयों द्वारा अपराध की सजा दी गई है, लेकिन न्याय की विफलता के लिए अनुकूल कुछ गंभीर कारक हमें अपवाद बनाने के

लिए प्रेरित करते हैं। अभियुक्त नकद रजिस्टर में उसी दिन बी. डी. ओ. के हस्ताक्षर के साथ समकालीन प्रविष्टि के कारण उचित संदेह के लाभ का हकदार है, जबकि बाद में उसका इप्सी डिक्सिट था। [689 जी, 691 एच, 692 जी-एच]

(2) हमारी टिप्पणियों को सफेदपोश अपराधों पर विफल रणनीतियों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। कार्यालय में रहने वालों द्वारा सार्वजनिक धन को संभालने में घोर लापरवाही, यहां तक कि पुरुषों की अनुपस्थिति में भी दंडात्मक परिणाम भुगतने चाहिए क्योंकि इससे गरीब जनता को दोहरी चोट पहुंचती है। [694 जी-एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या- 310/1971

उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपराधिक अपील सं. 168/69 और आपराधिक अपील संख्या 986/69 के विशेष अनुमति द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 23-4-1971 से।

अपीलार्थी के लिए फ्रैंक एंथनी और यू. पी. सिंह।

ओ. पी. राणा, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

कृष्णा आयर, जे.-

कुछ अपवाद इस नियम का खंडन करते हैं। ऐसे मामले लीजन होते हैं जहां तथ्य के निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय स्तर पर मुकदमेबाजी की अंतिमता के प्रस्ताव की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन नियम को साबित करने वाले अपवाद भी अच्छी तरह से स्थापित हैं।

हमें शुरुआत में यह कहना चाहिए कि यह मामला पारंपरिक कानूनी सांचे में फिट नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी, इसमें ऐसी अजीब विशेषताएं हैं कि हमारी 'अंतिम' शक्ति वैध रूप से काम में आ सकती है।

(शाहजहांपुर जिले में) एक ग्रामीण खंड विकास अधिकारी में एक छोटी सी दुकान के रखवाले-सह-कैशियर पर 5,000/-रुपये से थोड़ी अधिक राशि के गबन का आरोप लगाया गया था। आरोपों से इनकार किए जाने और वास्तविक अपराधी को खंड विकास कार्यालय के प्रमुख के रूप में इंगित किए जाने के बाद, सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों से साक्ष्य प्राप्त किए, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ, संक्षिप्त रूप से) की गवाही को गबन की कई वस्तुओं के संबंध में पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य पाया और कई कदाचारों के संबंध में उनकी दोषीता के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। हमारे पास 'स्मॉल फ्राई' के पकड़े जाने और आर्थिक अपराधों में बड़ी शार्क के जाल तोड़ने की असामान्य घटना के बारे में कुछ कहने के लिए हो सकता है जहां सार्वजनिक धन को लोक सेवकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुछ समय के लिए हम इस बयान से संतुष्ट हो सकते हैं कि तीस साल के छोटे अधिकारी-जो आरोपी था-को एक आरोप और 5, 194.82 रुपये के गबन के अलावा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था 50/- रुपये की एक भगोड़ी वस्तु में बदल गया। जिसके लिए उसे एक साल के कारावास और 300/- रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी। दोषसिद्धि की पुष्टि हो गई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने सजा को कम कर दिया था।

पीड़ित अपीलार्थी हमारे समक्ष आग्रह करता है कि गबन की एकमात्र बची हुई वस्तु समवर्ती रूप से साबित हुई थी, वास्तव में, इस प्रक्रिया में मौलिक खामियों से दूषित हो गई थी। हम संक्षिप्त रूप से प्रकरण का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और

असाधारण विशेषताओं की दृढ़ता की जांच करेंगे जो उत्तेजक अगली कड़ी की ओर ले जाती हैं।

भारतीय पिछड़ेपन की कृषि संबंधी विशालता को खंड-स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों द्वारा समाप्त करने की कोशिश की जाती है। जैतिपुर ब्लॉक ऐसा ही एक ब्लॉक है और इसमें छोटे अधिकारियों और कुछ ग्रामीण विकास सहायकों का केंद्र है, जिसका वर्चस्व बीडीओ में निहित है। यहाँ के व्यक्ति आरोपी, स्टॉक-क्लर्क-कम-कैशियर, बीडीओ (पीडब्लू 8) और पंचायत सचिव (पीडब्लू 7) हैं जिनका शानदार वेतन रु 50/- प्रति माह।

अभियोजन पक्ष का विवरण लंबा चलता है लेकिन छोटा हो सकता है अगर हम आरोपों की बहुलता को छोड़ दें और तथ्यों को 50/-रुपये की एकल वस्तु तक सीमित कर दें। संक्षिप्त में, जैतिपुर में एक ब्लॉक कार्यालय था जहाँ एक छोटा कर्मचारी ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कम वेतन पर काम करता था। अभियुक्त कैशियर होता था और उसे बड़ी और छोटी राशि के साथ इस तरह की क्षमता सौंपी जाती थी। मामला, जैसा कि मूल रूप से अनुमान लगाया गया था, यह था कि रूपये 5,194.82 उसकी हिरासत के लिए प्रतिबद्ध था और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के विभिन्न कृत्यों द्वारा पूरी राशि उसकी अपनी जेब में डाल दी गई थी। मान लीजिए कि यह आरोपी कैशियर का कर्तव्य था कि वह कैश बुक को बनाए रखे और धन के साथ व्यवहार करे। समान रूप से यह तथ्य स्पष्ट है कि कार्यालय के प्रमुख, बीडीओ, 'संबंधित वाउचर के साथ नकद पुस्तिका की दैनिक प्रविष्टियों का मिलान और जांच करने, अपने हस्ताक्षर लगाने के लिए... दिन के अंत में कुल की जांच करने के बाद' कर्तव्यबद्ध थे।

प्रखंड कार्यालय में पंचायत सचिवों को कम वेतन मिलता है। उनमें से एक पीडब्लू 7 है, जो 50 रुपये के मासिक वेतन पर है। इन कार्यालयों की एक और

दुर्भाग्यपूर्ण विशेषता, जैसा कि साक्ष्य में खुलासा किया गया है, यह है कि इन छोटे वेतनों का भी अनियमित रूप से भुगतान किया जाता है, जिससे असंतोष और हेरफेर के लिए झुकाव दोनों पैदा होते हैं। सार्वजनिक कार्यालयों को इस तरह से चलाया जाना बहुत मानार्थ नहीं है। वैसे भी, पीडब्लू 7 को 22 फरवरी, 1965 को दिसंबर 1964 के लिए उनका वेतन मिला और जनवरी 1965 के बाद के महीने के लिए उनका वेतन उन्होंने कुछ दिन पहले 15 फरवरी, 1965 को प्राप्त किया (प्रदर्शनी का 26 और का 29 के माध्यम से)। संवितरण में इन विषमताओं के कारण आरोपी असलम ने प्रशंसनीय याचिका दायर की कि पी. डब्ल्यू. 7 ने जनवरी आने और जाने के बाद भी दिसंबर 1964 के महीने के लिए अपना मामूली धन प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसने धन की सख्त आवश्यकता का अनुरोध किया और जनवरी 1965 के महीने के वेतन के रूप में 50/- रुपये प्राप्त किए और उस पर 1 फरवरी, 1965 तारीख वाले एक अलग वाउचर पर हस्ताक्षर किए। यह कल्पना की जा सकती है कि एक छोटा सा आदमी, जिसके पास थोड़े से वेतन का पैकेट है, कैशियर पर दबाव डालता है कि वह उसे एक वाउचर पर हस्ताक्षर करने के लिए छोटी राशि का भुगतान करे और अगर कैशियर करुणा के आगे झुक जाता है और भुगतान करता है तो हमें आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक यही मामला अभियुक्त का है।

इस याचिका को समर्थन देने के लिए, वह 1 फरवरी, 1965 की तारीख के खिलाफ नकद रजिस्टर में एक नियमित प्रविष्टि की ओर इशारा करते हैं, जिसमें जनवरी 1965 से पीडब्लू 7 के महीने के लिए वेतन के रूप में 50/- रुपये का भुगतान किया गया था। सुदृढीकरण इस तथ्य से प्राप्त होता है कि भुगतान की यह विशिष्ट प्रविष्टि- जिसका मिथ्याकरण 50 रुपये के गबन के आरोप की नींव है, बी. डी. ओ. पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा शुरू की गई है। हमने पहले इस अधिकारी की प्रथा और दायित्व का उल्लेख किया है कि वह संबंधित वाउचर के साथ कैश बुक में दैनिक प्रविष्टियों का मिलान और

जांच करे और फिर दिन के अंत में कुल की जांच करने के बाद हस्ताक्षर करे। इसके अलावा उनके पास विशेष जिम्मेदारी थी, अपने स्वयं के प्रदर्शन पर कर्मचारियों के सबसे जिम्मेदार अधिकारी के रूप में, 'हर दिन के अंत में पाए जाने वाले नकद शेष को कैश-चेस्ट रजिस्टर में रखना'। वह नकदी का दैनिक भौतिक सत्यापन नहीं करता है, लेकिन इसे मासिक आधार पर करता है और वह इसकी चाबी रखता है, हालांकि एक और चाबी कैशियर के पास रह जाती है।

अभियुक्त का यह तर्क कि उसने 1 फरवरी, 1965 को पी. डब्ल्यू. 7 को 50 रुपये का वेतन दिया था, समर्थित है, हालांकि यह बी. डी. ओ. द्वारा विधिवत शुरू की गई पुस्तकों में एक प्रविष्टि द्वारा है, संभवतः संबंधित वाउचर के साथ सत्यापन के बाद अदालतों द्वारा इन परिस्थितियों का विज्ञापन किए बिना इस सतही याचिका द्वारा खारिज कर दिया गया है कि पी. डब्ल्यू. 7 को 22 फरवरी, 1965 को दिसंबर 1964 के लिए नियमित प्रविष्टि और एक मुहर वाले वाउचर के साथ वेतन का भुगतान किया गया था। पी. डब्ल्यू. 7 ने जब जाँच की, तो संदिग्ध स्पष्टता के साथ 1 फरवरी को पहले के भुगतान से इनकार कर दिया और 22 फरवरी, 1965 को मुहरबंद वाउचर द्वारा समर्थित दिसंबर के भुगतान का स्वामित्व लिया। रहस्य की एक लकीर पी. डब्ल्यू. 7 की गवाही में संदेह पैदा करती है क्योंकि प्रतिपरीक्षा में वे कहते हैंः "" "मुझे ऐसा याद नहीं है कि अन्य अधिकारियों के साथ, कैशियर ने मुझे गलती से दो बार जनवरी 1965 के महीने का वेतन दे दिया होगा।" अगली सांस में वह खुद को यह कहने के लिए सही करता है कि उसे दो बार भुगतान नहीं किया गया था। इन सामग्रियों के बल पर दोनों न्यायालयों द्वारा अपराध की दोषसिद्धि प्रदान की गई है और, चाहे प्रशंसा सही हो या गलत, हमें अंतिम न्यायालय के रूप में पुनर्मूल्यांकन के प्रलोभन से सामान्य रूप से पीछे हटना चाहिए था, जोरदार तर्क के बावजूद। लेकिन कुछ गंभीर कारक, जो न्याय की विफलता

के लिए अनुकूल हैं, हमें एक अपवाद बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिन पर हम वर्तमान में विस्तार करेंगे।

मूल रूप से अभियुक्त पर गबन के नौ आरोप लगाए गए थे। सभी, एक को छोड़कर, अप्रमाणित रहे और अपराध अब एक महत्वहीन वस्तु पर तय हो गया है। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक धन की सबसे छोटी राशि को दंड से मुक्ति के साथ निजी तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन यह कि सभी प्रमुख मदों के संबंध में अपना मामला बनाने में अभियोजन पक्ष की पर्याप्त विफलता से परिप्रेक्ष्य कुछ हद तक रंगीन हो जाता है। अधिक परेशान करने वाला तथ्य यह है कि एकमात्र जीवित आरोप परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य के प्रकाश में सराहना किए गए एकल गवाह की सत्यता या असत्यता पर खड़ा है या गिरता है। वे परिस्थितियाँ क्या हैं? बीडीओ, जिस पर संस्थान के वित्त पर संरक्षक कार्यों सहित गंभीर जिम्मेदारियां हैं, ने शपथ ली है कि वह संबंधित वाउचर के साथ कैश बुक में दैनिक प्रविष्टियों की जांच करता है और अपने हस्ताक्षर लगाता है, दिन के अंत में कुल की जांच करता है और फिर से अपने हस्ताक्षर लगाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि 1 फरवरी, 1965 को नकद पुस्तिका में एक विशिष्ट प्रविष्टि है कि पीडब्लू 7 को वेतन के रूप में 50 रुपये का भुगतान किया गया है। बी. डी. ओ. ने प्रविष्टि के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं जिसका अर्थ है, सामान्य रूप से, उन्होंने संबंधित वाउचर के संदर्भ में भुगतान को सत्यापित किया है। यदि यह एक तथ्य है, तो अभियुक्त ने शायद वेतन का भुगतान किया है, आवश्यक प्रविष्टि की है, इसे बीडीओ को प्रासंगिक वाउचर के साथ दिखाया है, अपने हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, आंकड़ों को सही ढंग से जोड़ा है और बीडीओ के हस्ताक्षर को फिर से सुरक्षित किया है। आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य नियमों के अनुसार, अभियुक्त को दोषसिद्धि से मुक्त करने के लिए इस गवाही का दंडात्मक प्रभाव पर्याप्त है क्योंकि उचित संदेह उत्पन्न होता है। अपराध के बारे में विवेकपूर्ण संदेह जो प्रासंगिक प्रविष्टि के खिलाफ बीडीओ के हस्ताक्षर से उत्पन्न होता

है, इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में संदर्भित वित्त पुस्तिका में कहा गया है कि यह आहरण और वितरण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह नकद पुस्तिका में दर्ज रसीद और व्यय की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच करे और समय-समय पर नकद शेष राशि की भौतिक रूप से जांच करे। उच्च न्यायालय के अनुसार, बीडीओ ने कुछ तथ्यों को दबाने के लिए टालमटोल वाले बयान दिए हैं और 'कुछ स्पष्ट झूठ बोले हैं'। आश्चर्यजनक रूप से, सत्र न्यायालय ने पी. डब्ल्यू. 8, बी. डी. ओ. को कुछ अन्य आरोपों के संबंध में गलत और अविश्वसनीय के रूप में दर्ज किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोपों के रूप में चार प्रविष्टियां वास्तव में बी. डी. ओ. को दी गई थीं 'जिन्होंने शायद इन राशियों का गबन किया'। इन चार आरोपों पर अभियुक्तों के परिणामी बरी होने के फैसले में कोई बाधा नहीं आई है। संक्षेप में, इसलिए, यह निष्कर्ष अटूट है कि बीडीओ, पूर्ण वित्तीय नियंत्रण में शीर्ष अधिकारी, ने ब्लॉक कार्यालय के धन के संबंध में गैर-जिम्मेदाराना या अपराधपूर्ण व्यवहार किया था, जिसे इतना झूठा बताया गया था कि उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता था और उसने अपने मुँह से नकदी रजिस्टर की जांच के संबंध में सार्वजनिक कर्तव्य की घोर उपेक्षा के लिए खुद को दोषी ठहराया था। यदि हम संलग्न करते हैं, तो अदालत के लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं है-उसी दिन बी. डी. ओ. के हस्ताक्षर के साथ नकद रजिस्टर में अवमानना प्रविष्टि को महत्व न दिया जाए, क्योंकि बाद में अभियुक्त उचित संदेह के लाभ का हकदार है। 50 रुपये के भुगतान का प्रमाण देने वाला एक अलग वाउचर होने की संभावना है जो अवमूल्यन का विषय है क्योंकि बीडीओ ने संबंधित रसीद के साथ जाँच किए बिना उस भुगतान की प्रविष्टि को सत्यापित करने की संभावना नहीं है।

प्रोबेटिव बैलेंस-शीट को लागू करने से पहले दो परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। 1 फरवरी, 1965 को 50 रुपये की प्रविष्टि बंद होती दिखाई देती है। यह

किसने किया? क्या हम अंधेरे में अनुमान लगा सकते हैं? अभिलेख पर कुछ भी नहीं बताता है कि अकेले अभियुक्त ही ऐसा कर सकता था। इस सिद्धांत में बहुत अधिक विश्वसनीयता है कि बी. डी. ओ. और क्लर्क की मिलीभगत से छोटी राशियों को सार्वजनिक खजाने से चुपचाप निकाल लिया जाता है, विश्वास करें कि प्रविष्टियां की जाती हैं और बी. डी. ओ. द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और यदि उच्च अधिकारियों द्वारा पता लगाने के खतरे को पकड़ा जाता है, तो परिवर्धन, परिवर्तन और इसी तरह के काम किए जाते हैं। यह आम बात है कि कैश रजिस्टर में इस तरह के कई क्रॉसिंग, कटिंग, स्कोरिंग और इस तरह की छेड़छाड़ होती है। कई बलि-अनुग्रह शायद इन प्रक्रियाओं के पक्षकार थे लेकिन एक बलि का बकरा, उस कारण से, आपराधिक अदालत में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

इस संदर्भ में यह याद रखना उचित है कि जिला लेखाकार ने ब्लॉक कार्यालयों की पुस्तकों की पूरी तरह से जांच करने के बाद कहा है कि बीडीओ की शिथिलता के कारण कई गबन किए गए हैं, जिन्हें नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। बीडीओ के खिलाफ और कैशियर के खिलाफ विभागीय रूप से आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा एक और सिफारिश भी रिपोर्ट में पाई गई है। क्या बी. डी. ओ. के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, राज्य का वकील हमें यह नहीं बता सका।

आरोपित आपराधिकता के लिए एकमात्र मौखिक सेवा पीडब्लू 7 द्वारा दी जाती है। क्या उन्हें दो बार 50 रुपये का वेतन मिला? निस्संदेह वह इसे अस्वीकार करने में रुचि रखते थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें अपना 50 रुपये का छोटा दिसंबर वेतन केवल अगले फरवरी में मिला। बहुत अधिक संभावना है कि ऐसी स्थिति में उन्होंने 50 रुपये के भुगतान को बाद में समायोजित करने के लिए दबाव डाला होगा। इसी तरह, इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार करने में कि उन्हें दो बार भुगतान

किया गया था, उनकी प्रारंभिक अस्पष्टता इस संदेह को बढ़ाती है। जब कार्यालय के नकदी मामले गड़बड़ में होते हैं, जब प्रमुख लापरवाही का दोषी होता है, जब क्लर्क अनियमित अंतराल पर छोटे वेतन प्राप्त कर रहे होते हैं, तो पीडब्लू 7 की कुछ हद तक दागी गवाही बहुत मोटी होती है, क्योंकि यह बीडीओ द्वारा नकद रजिस्टर प्रविष्टि के खिलाफ है, जाहिरा तौर पर भुगतान वाउचर से परामर्श करने के बाद। अभियुक्त को तुरंत निलंबित कर दिया गया था और इसलिए यह वाउचर, यदि यह मौजूद था, तो कार्यालय में होना चाहिए और अदालत में इसे पेश न करना अभियुक्त के खिलाफ निष्कर्ष निकालने का मामला नहीं है।

हमने साक्ष्य का यह असामान्य प्रोबेटिव सर्वेक्षण केवल इस कारण से किया है कि अभियोजन पक्ष की ईमानदारी, बड़े को छोड़ना और छोटे पर जाना, झूठी गवाही को सच के साथ जोड़ना गंभीर रूप से संदिग्ध है और आरोपी की दोषसिद्धि को बिना किसी सबूत के बनाए रखना, जिस पर कानून में उचित रूप से निर्देश दिया गया व्यक्ति भरोसा करेगा, न तो न्यायसंगत है और न ही कानूनी है।

अपराध के समय, आरोपी अपने शुरुआती बिस के दशक में था, शायद एक छोटे से रैकेट में एक नवजात या नया प्रवेशकर्ता था। संदेह तब उसकी संलिप्तता के बारे में होते हैं लेकिन यह कि एक आदमी दोषी हो सकता है, यह कहने से अलग है कि उसे दोषी होना चाहिए। दोनों के बीच विभाजन रेखा कभी-कभी ठीक होती है, लेकिन हमेशा वास्तविक होती है। खंड विकास कार्यालय के संचालन में संयुक्त अपराध में निस्संदेह सामूहिक अपराध है। सार्वजनिक मामलों और सार्वजनिक धन, विशेष रूप से विकास के मोर्चे पर, कहीं अधिक ईमानदारी, व्यवस्था, सक्रियता और वित्तीय विवेक की आवश्यकता होती है। इसकी अनुपस्थिति में हमें खेद है, लेकिन विशेष अभियुक्त का विशिष्ट अपराध

साबित नहीं हुआ है, जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है, जिसके परिणामस्वरूप उसे बरी कर दिया गया है।

हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं। अपराध का पता लगाने का कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन न्यायाधीशों की देश के प्रति उस हद तक जवाबदेही होती है जब तक कि उनकी पेशेवर जांच के दायरे में आने वाले मामले स्पष्ट होने के लायक नहीं होते हैं। इस बहाना के साथ हम कुछ अवलोकन करते हैं।

सार्वजनिक धन के लिए खुद को छोटे टुकड़ों या बड़े टुकड़ों में मदद करने की लोकप्रिय कला एक आधिकारिक विकृति है जिसका विनाशकारी दौर लोक कल्याण संस्थानों में काफी विस्तार और ग्रामीण विकास के लिए खर्च के साथ फैल गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर गुन्नार मिरदाल के एशियन ड्रामा तक, सार्वजनिक कार्यालयों में इन बुराइयों को मिटाने के लिए आपराधिक अभियोजन की परियोजनाओं में भारी गिरावट यह है कि अक्सर इन असामाजिक योजनाओं के बड़े इंजीनियर अभियोजन गवाह के रूप में दिखाई देते हैं और पैकेज सौदे में छोटे लोगों को बलि देने वाले बकरों के रूप में रखा जाता है। सिर भाग जाता है, हाथ का पीछा किया जाता है और जब अदालत दोषी ठहराती है, तो निंदा के बजाय सनकीपन, अनपेक्षित सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती है। उच्च और निम्न की सामाजिक प्रणाली में, जहां दंडात्मक प्रक्रियाओं के पहियों को पूर्व द्वारा संचालित किया जाता है, चेहरे पर समान कानून दिल से असमान होते हैं। क्रैक-डाउन अपराध नियंत्रण स्वयं सार्वजनिक शक्ति की एजेंसियों के सामाजिक दर्शन से अपना संरेखण लेता है। वर्तमान मामला एक फैलने वाली बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है और राज्य, अपने उच्चतम स्तर पर, आर्थिक अपराधों के इस रॉकेट को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, व्यक्तिगत पदों की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर, त्वरित कार्रवाई, व्यापक स्पेक्ट्रम अभियोजन उपचार शुरू करना चाहिए, और

आराम से प्रक्रियात्मक उपकरण, यदि उच्च सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। संदिग्ध अधिकारी को गवाह-बक्से में सच्चाई विक्रेता और सहयोगी अनुचर को गोदी-निवासी बनाने का रहस्य, ऊपरी-बर्थ अपराधी को शरण देने की साजिश के रूप में संदेह है। सीज़र की पत्नी, जहाँ सार्वजनिक हित दांव पर है, संदेह से परे होनी चाहिए, अगर अभियोजन की विश्वसनीयता लोकप्रिय खरीद है।

यदि समाजवाद के लिए तैयार राष्ट्र को सार्वजनिक कार्यालय के अपराधों पर शून्य-इन करना चाहिए, तो जो हमने देखा है वह नहीं होना चाहिए-और निश्चित रूप से, आज्ञाकारी उपदेशों के रूप में नहीं सोएगा, बल्कि सफेदपोश अपराधों पर रणनीतियों को ध्वस्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। दुर्लभ संसाधनों वाले एक विकासशील देश में, सार्वजनिक धन को संभालना एक विशेष बोझ है। पद पर बैठे लोगों द्वारा राष्ट्र की संपत्ति को संभालने में घोर लापरवाही, यहां तक कि पुरुषों की अनुपस्थिति को भी आपराधिक दायित्व के साथ देखा जाना चाहिए क्योंकि यह उस बेजुबान, बेजुबान, दुखी समुदाय को दोहरी चोट पहुंचाता है-जो कि बहुतायत में नहीं है। यदि भारतीय क्षेत्राधिकार को विकासात्मक कानून के माध्यम से अपने सामाजिक मिशन को पूरा करना है, तो दंड कानून के तहत सार्वजनिक शक्ति को उच्च स्तर की देखभाल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि ऐसा कानून मौजूद होता, तो कई वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से बड़ी राशि या बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते, संभावित दंडात्मक परिणाम से बेहतर मानकों में बदल सकते थे। वर्तमान मामला एक उदाहरण है और हमें उम्मीद है कि हमारे सांसद सुनेंगे।

एम. आर.

अपील को अनुमति दी गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।